

संख्या-- 990 / 69-1-12-14(97) / 07

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

994/dk
13/7/12

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2012

विषय- जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा कार्य निष्पादन की वित्तीय सीमा कम किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-527/07/76/एक/ 12-13, दिनांक 05 जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०एच०एस०डी०पी०/बी०एस०यू०पी० की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वीआईपी-30/69-1-09-14(97)/07, दिनांक 28.08.2009 द्वारा रू० 4.00 करोड़ तक की परियोजनाओं में निर्माण कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा किये जा सकने की अनुमति प्रदान की गई थी। इससे अन्य विभागीय कार्यों में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की क्षमता का पूर्णरूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व की भाँति रू० 2.00 करोड़ तक की परियोजनाओं में निर्माण कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा किया जा सकेगा। उक्त सीमा से अधिक के कार्य वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-667/दस-06-89/04, दिनांक 06 जून, 2006 व उसके अनुवर्ती शासनादेशों में वर्णित कार्यदायी संस्थाओं से ही कराये जाये। शासनादेश संख्या-वीआईपी 30/69-1-09-14(97)/07, दिनांक 28 अगस्त, 2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रो. अशोक शर्मा
13/7/12

निदेशक, उ०प्र०

महोदय के आग्रह कि कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विभागीय वेबसाइट पर

प्रकाशित प्रलेख अ. अ. अ.

C:\NR-NGO

12/7/12

(आर० पी० सिंह)
उप निदेशक

नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
उ०प्र० शासन।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

12/7/12

(प्रवीर कुमार)